



2026:AHC:165688

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26604 वर्ष 2026

संजय कुरैशी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : रघुबीर सिंह
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रघुबीर सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष कुमार त्रिपाठी को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 125 वर्ष 2026, धारा 70(1), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत, थाना फतेहपुर सीकरी, जनपद आगरा में पंजीकृत मामले में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है तथा पीड़िता बालिग महिला है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना की कथित तिथि को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया और उसी दिन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत उसका कथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त कासिम उससे मिले और आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया तथा सह-अभियुक्त पहरा देता रहा। अतः उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 4.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसके विरुद्ध सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें से सभी मामलों में वह जमानत पर है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 19 वर्ष की आयु की पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना बताया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि यदि अभियुक्त को पीड़िता के समक्ष लाया जाएगा तो वह उसकी पहचान कर लेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दर्ज की गई है तथा पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया और उसी दिन उसका कथन भी दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत अपने कथन में उसने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत अपने कथन में उसने कहा है कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त हाशिम उससे मिले और आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया तथा सह-अभियुक्त पहरा देता रहा। आवेदक 4.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसके विरुद्ध सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें से सभी मामलों में वह जमानत पर है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक- **संजय कुरैशी**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।